देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 13.11.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने 28 नर्सिंग अधिकारियों और 14 सीएमएसडी टैक्नीशियन को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा– प्रदेश सरकार, राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिये प्रतिबद्ध।
- दिल्ली विस्फोट की घटना के बाद बदरीनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। ड्रोन की मदद से भी की जा रही निगरानी।
- प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अन्तर्गत देहरादून जिला प्रशासन सरकारी स्कूलों को सुविधा सम्पन्न बना रहा है।
- पौड़ी जिले के पोखड़ा में बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अफसर बिटिया कार्यक्रम का आयोजन।

नियुक्ति पत्र

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित 28 नर्सिंग अधिकारियों और 14 सीएमएसडी टैक्नीशियन को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके अलावा उन्होंने छह एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग और एक प्रोफेसर नर्सिंग को भी नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नर्सिंग अधिकारी और सीएमएसडी टैक्नीशियन की नियुक्ति से राजकीय मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। साथ ही मरीजों को उनकी बीमारियों से संबंधित पैथोलॉजी जांचे भी समय पर मिल सकेगी। जबकि राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर की नियुक्ति होने से जहां सकाय सदस्यों की कमी दूर होगी। वहीं नर्सिंग छात्र–छात्राओं को बेहतर शिक्षण–प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार, राज्य के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने व प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिये प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. रावत ने राजकीय स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में निर्मित व्याख्यान कक्षों व लैब का लोकार्पण भी किया।

बदरीनाथ सुरक्षा

दिल्ली विस्फोट की घटना के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के सभी जिलों में अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमाओं, संवेदनशील स्थलों, धार्मिक स्थलों, बाजारों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, मॉल और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन चेकिंग की जा रही है। वहीं, चमोली जिले में स्थित बदरीनाथ धाम में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि रात में धाम के कपाट बंद होने के बाद किसी भी व्यक्ति को मंदिर परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मंदिर, धर्मशालाओं, होटलों, ढाबों की गहन तलाशी जारी है। सेना और पुलिस संयुक्त रूप से गश्त कर

रही है। वहीं ड्रोन कैमरो से भी धाम की निगरानी की जा रही है। साथ ही संदिग्धों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।

आपदा प्रबंधन तैयारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. डी.के. असवाल ने उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का दौरा कर आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य की भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए समग्र आपदा प्रबंधन नीति तैयार करने के निर्देश दिए।

डॉ. असवाल ने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में विकास और आपदा प्रबंधन के बीच संतुलन आवश्यक है। उन्होंने ऐसी दूरदर्शी नीति बनाने पर जोर दिया, जो विकास के साथ आपदा जोखिम को कम करने पर भी समान ध्यान दे।

बैठक

बागेश्वर की जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त सभी शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेकर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों की नियमित निगरानी की जाए और उत्तराधिकारियों को उनकी प्रगति की जानकारी दी जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन उत्तराधिकारियों के पेंशन या परिचय पत्र लंबित हैं, उनकी प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाए। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को आदेश दिए कि 25 दिसम्बर तक सभी ग्राम पंचायतों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम शिलापटों पर अंकित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अलावा उन्होंने शहीद स्मारक पर छत निर्माण और नाम सत्यापन कर नए नाम जोड़ने के निर्देश भी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को दिए।

प्रोजेक्ट उत्कर्ष

प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत देहरादून जिले के सरकारी स्कूलों को सुविधा सम्पन्न किया गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल स्वयं इन कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। देहरादून प्रशासन की ओर से बताया गया है कि प्रोजेक्ट 'उत्कर्ष' के माध्यम से जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम, लाईब्रेरी, वाइट बोर्ड, खेल मैदान और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक विद्यालयों में बेबी स्लाईड, झूले, माध्यमिक विद्यालयों में वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हैं। प्रशासन ने ओएनजीसी के माध्यम से 34 विद्यालयों में फर्नीचर सेट, हुडको के माध्यम से 629 प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर सेट लगवाए हैं। जबकि, जिला खनिज न्यास से 39 प्राथमिक विद्यालयों और 80 माध्यमिक विद्यालयों के लिए फर्नीचर सेट प्रदान किए गए हैं। 168 विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग के लिए स्मार्ट टीवी लगाने की प्रक्रिया चल रही

है। जिले के तीन कस्तूरबा गांधी बोर्डिंग विद्यालयों को भी इस प्रोजेक्ट के तहत सुविधा संपन्न किया गया है। स्कूलों में सुविधाओं के लिए प्राजेक्ट उत्कर्ष अन्तर्गत जिलाधिकारी ने एक करोड़ रूपये की धनराशि मुख्य शिक्षा अधिकारी के अधीन रखी है।

अफसर बिटिया कार्यक्रम

पौड़ी जिले में बाल विकास परियोजना पोखड़ा के तत्वावधान में बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अफसर बिटिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी एकेश्वर हेमंती रावत ने कार्यक्रम के उद्देश्य और लक्ष्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि बालिकाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही सशक्त समाज की नींव है। उन्होंने छात्राओं से जीवन में लक्ष्य निर्धारण कर निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान अन्य विभागों से आए अधिकारियों और कर्मचारियों ने छात्राओं को प्रेरणादायक व्याख्यानों के माध्यम से अफसर बिटिया बनने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रमाणपत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए।

जनसेवा केंद्र

प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से मिलने वाले प्रमाण पत्र को लोग घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर प्राप्त कर सकते है। साथ ही किसी समस्या पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इसी क्रम में हरिद्वार जिले के विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अब जन सेवा केंद्रों का लाभ उठा रहे हैं। तहसीलदार सचिन कुमार का कहना है कि तहसील में 8 से 10 प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा दी गई है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जन सेवा केंद्र वरदान साबित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोग अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करके वहीं से प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे अब उन्हें बार–बार तहसील और सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती है।

मिस्सरपुर ग्राम सभा के प्रधान पंकज चौहान का कहना है कि जन सेवा केंद्र शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए भी मददगार साबित हो रहे हैं।